

15/5/18

पञ्जाबी पेशा उभय पक्ष के अधिकारियों  
 उपरोक्त वरुदा उभय पक्ष आवेदन  
 अन्तर्गत धारा 151 CPC बाबत  
 प्रेषणीयता सुनी गई। प्रार्थना रीत्यो.  
 ने आवेदन अन्तर्गत धारा 151 CPC  
 प्रस्तुत का उल्लेख किया कि उनानी  
 प्रमाण में अपीलार्थ द्वारा तहसीलदार सीमा  
 के निर्णय के विरुद्ध एक अपील न्यायालय  
 जिला मन्सूर सीमा के समक्ष धारा  
 225 RT Act के तहत प्रस्तुत की  
 जिसे न्यायालय जिला मन्सूर द्वारा  
 दि-20/2/18 को खारिज म डिजिट  
 गया। इस निर्णय की अपील पुनः  
 धारा 225 RT Act के तहत प्रस्तुत  
 की गई जो विधि विरुद्ध पेश की  
 गई है तथा न्यायालय द्वारा  
 के अधिकाधिकार में नहीं होने  
 के कारण प्रेषणीय नहीं होने के  
 कारण खारिज भी गई।  
 अपीलार्थ ने प्रार्थना पत्र के  
 जवाब नहीं देकर सीधे ही वरुदा  
 की। कानून का निवेदन किया।



6/5/18 - मं. मं. - 35/19  
 जिला मन्सूर - मन्सूर

जिला मन्सूर  
 पंजाब  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी एवं  
 जिला मन्सूर

PTD



में अति तथ्यों को लेकर हुए फंडा  
वि धारा 225 RT Act के अंतर्गत  
के विरुद्ध रिवीजन का स्पष्ट प्रावधान है  
न्यायालय RAA में डिप्लोम इपील

इपीलेट डिप्लोम की धारा 224 RT Act  
के तहत पेश की जा सकती है।

निगराही का स्पष्ट प्रावधान होने के  
बावजूद अपीलेंट द्वारा विधि विरुद्ध  
तरीके से इपील पेश की गई है।

जो कि खारिज किए जाने योग्य है।  
अतः इपील को पोलीमल में  
इमान में खारिज की जावे।

दोसरे पहलु वकील इपीलेट  
ने जस्टि किम कि न्यायालय धारा  
में इपील सही रूप से पेश की

गई है। न्यायालय के अंतर्गत  
है। अतः इपील आवेदन खारिज  
किया जावे।

आवेदन का आवेदन किम। रिमार्क  
का आवेदन किम। उच्च पक्षों की

वहल पर गौर किम। गणा।  
प्रमाण के तथ्यों में शुभ तथ्योक्त  
द्वारा 183 B RT Act के तहत न्यायालय


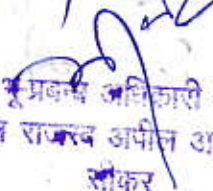
का निर्णय पारित किम। जिला। उच्च  
इपील 225 RT Act के तहत

जिला काउन्सिल को की गई। अब  
इस आदेश के विरुद्ध & रिवीजन  
ही की जा सकती है। न्यायालय

हालांकि में 225 RT Act के  
तहत जिला काउन्सिल के निर्णय

के विरुद्ध इपील पेश नहीं की  
जा सकती है।

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom left corner.

दिनांक	आज्ञा पत्र
	<p>द्वितीय अपील अपील नंबर 131 की धारा  <del>धारा 224 RT Act</del>  तहत प्रेष की जा रही है।  इस तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में  प्रार्थी का आदेश कानूनन धारा  151 CPC पोषणीयता के संबंध  में स्वीकार किया जाता है तथा  अपील अपील नं. 131 का  के अतिरिक्त में नहीं होने के  कारण पोषणीय नहीं होने के कारण  स्वीकार की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">   मुख्य अधिकारी एवं  एडवोकेट राजशेखर अपील अधिकारी  साकर </p>